



भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ

Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-11, Aligarh, Lucknow-226024, Telefax-22266776
E-mail: ec@moef.gov.in, ec@moef.nic.in, ec@moef.gov.in

पत्र सं० 8बी/यूपी०/०४/१००/२०१६/एफ सी/435

दिनांक 07.10.2021

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी
17 राणा प्रताप मार्ग
लखनऊ-७०५०१

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/TRANS/21588/2014

विषय: 800 कें०वी० एच०वी०डी०सी० चम्पा-कुरुक्षेत्र पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मैनपुरी में प्रभावित ०.9591 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 142 वृक्षों के पातन, एटा में प्रभावित 0.5658 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 20 वृक्षों के पातन, कासगंज में प्रभावित 0.9315 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 159 वृक्षों के पातन, अलीगढ़ में प्रभावित 0.4457 हे० एवं उस पर अवस्थित 211 वृक्षों के पातन एवं बुलन्दशहर में प्रभावित 0.8073 हे० संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 44 वृक्षों के पातन कुल 3.7094 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित कुल 576 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक ०-813/11-सी-FP/UP/Trans/21588/2014, लखनऊ, दिनांक-13.09.2021

महोदय

कृपया उपरोक्त विषय पर उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-941/चम्पा-कुरुक्षेत्र लाइन (समेकित), लखनऊ, दिनांक-28.10.2016 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयावित्त प्रस्ताव पर वन(संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कायालय के समसूचक पत्र दिनांक 09.10.2019 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसकी उल्लिखित शर्तों की अनुपालना उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारापरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार 800 कें०वी० एच०वी०डी०सी० चम्पा-कुरुक्षेत्र पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मैनपुरी में प्रभावित 0.9591 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 142 वृक्षों के पातन, एटा में प्रभावित 0.5658 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 20 वृक्षों के पातन, कासगंज में प्रभावित 0.9315 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 159 वृक्षों के पातन, अलीगढ़ में प्रभावित 0.4457 हे० एवं उस पर अवस्थित 211 वृक्षों के पातन एवं बुलन्दशहर में प्रभावित 0.8073 हे० संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 44 वृक्षों के पातन कुल 3.7094 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित कुल 576 वृक्षों के पातन की विधायक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 3.7094x2=7.4188 ha. degraded forest land in Aligarh, Kasganj, Mainpuri, Bulandshar, Etah Forest Division at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. No fast growing trees will be planted.
3. Plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in ROW under Transmission line shall be taken up by Forest Department at the cost of user agency.
4. The complete compliance of the F.R.A. 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.

5. The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.
6. The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05/05/2014 & 19/11/2014
7. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
8. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
9. No labour camp shall be established on the forest land.
10. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel
11. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
12. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
13. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
14. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
15. The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details.
16. The User Agency and the State Government shall ensure compliance of all the Court orders, provisions, rules, regulations and guidelines for the time being in force as applicable to the project.
17. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
18. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
19. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

भवदीया,



(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक(के०)

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :-

1. उम्मेदवार प्रमुख सचिव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार कायम जल-नक़्त।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(सहायक) वन विभाग, 17 बाग प्रताप मार्ग, जल-नक़्त (उ/प्र)।
3. प्रभागीय निदेशक मेनफुली एटा क्षेत्रगत अखीण्ड, इलाहाबाद।
4. मुख्य प्रबंधक, पारदर्शिता ऑफिस इन्डिया सि. 204-साई कटिका रमेश विहार के सामने सिविल लाईन अखीण्ड।
5. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जल-नक़्त की वेबसाइट पर अपलोडिंग 01/07/2024 तक।


07.07.2024
सचिव वन विभाग (उ/प्र)